श्री प्रेम गुप्ता:मान्यवर, फ्री ट्रेड के नाम पर जो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, बड़े गलत एग्रीमेंट हैं। गुजराल सरकार के टाइम में नेपाल सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था। उसको पूरी इंडियन इंडस्ट्री ने चार साल तक भुगता है और इंडियन इंडस्ट्री की क्या हालत है, आप तो जानते हैं। सर, 35 परसेंट कापर के अंदर वैल्यु एडिशन की जो आप बात कर रहे हैं? if possible? आप तो नामी-ग्रामी वकील हैं, सारे इश्यू को समझते हैं। आप इंडियन इंडस्ट्री को क्यों तबाह करवाने पर तुले हुए हैं? सर, यही अब हो रहा है, डीओपी में, कैमिकल इंडस्ट्री में भी अब शुरु हो गया है। नेपाल से पहले वनस्पति से शुरु हुआ था। एक किलोग्राम, एक ग्राम भी नेपाल में या श्रीलंका में कापर का ग्रेन नहीं होता है। वहां कोई माइनिंग़ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो प्रोडयूसिंग कंट्रीज हैं, चिली है, जाम्बिया है, वहां से जीरो एक्सपोर्ट है। You are making imports worth Rs. 300 to 400 crores from countries like Nepal, Sri Lanka, etc. You *tr* give them a grant so that our industries do not suffer. What are you क्या आपके अधिकारियों ने कभी सोचा है कि कापर में 35 परसेंट का वैल्यू एडिशन होता है?

श्री अरुण जेटली: सभापति जी, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है,हमारा सिर्फ लंका के साथ है। दूसरे प्रकार के एग्रीमेंट रीजनल श्रेत्रीय एग्रीमेंटस अन्य देशों के साथ भी होते हैं। जब भी ये, इस प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं तो अपनी अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा,यह भी मद्देनजर ...(**व्यवधान**)... मुझे पूरा उत्तर देने दीजिए। श्रीलंका का आपने जिक्र किया, इस एग्रीमेंट के बाद आज जो श्रीलंका से टोटल इम्पोर्ट हर कमोडिटी का हमारे देश में है, अगर मैं पिछले वर्ष के आंकड़े आपको दूं तो 321 करोड़ हैं और जो हमारा वहां पर सामान जा रहा है, वह 3000 करोड़ से अधिक है। इसलिए किसी एकाध कमोडिटी के अंदर इस प्रकार की जब चिंता आती है, उसमें इम्पोर्ट सर्ज होता है तो हम उस देश के साथ इसको लेते हैं लेकिन ओवर ऑल यह अर्थव्यवस्था के हित में जाता है। केवल उन्हीं देशों के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हम लोग करते हैं।

श्री प्रेम गुप्ता:सर,...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति: नहीं गुप्ता जी, अब नहीं। नेकस्ट क्वेश्चन।...(**व्यवधान**).... मेरे पास पांच मिनट हैं, पांच मिनट में क्वेश्चन निकालने हैं।

Development of small ports

*538. PROF. M. SANKARALINGAM:†

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU:

Will the Minister of SKIPPING be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a blue print to develop small ports in the entire Indian Peninsula to promote coasta! shipping;

† The question was actually asked on the floor of the House by Prof. M Sankaraiingam.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have appointed consultants to study the location of ports;

(d) if so, the details thereof submitted by them, specially locations identified in Tamil Nadu and Pondicherry; and

(e) whether Government have fixed any time-frame for the development of these small ports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI DILIP KUMAR MANSUKHLAL GANDHI): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) M/s. Tata Consultancy Services have been awarded a study on development of coastal shipping and minor ports. The term of reference of the study include identification of sites for possible establishment of ports for use by coastal shipping. The Agreement with the Consultant has been signed on 28.2.2003 and the report of the Consultant is likely to be received within seven months.

(e) No, Sir.

PROF. M. SANKARALANGAM: Sir, in the Minister's Statement, the first two questions have been replied in the negative. But Shri M.P. Pinto, Secretary (Shipping), while addressing a meeting of the Confederation of Indian Industry, had clearly stated that, for developing a string of small ports in the entire Indian Peninsula in order to promote coastal shipping, the Government was formulating a blue print. The reply given here is contrary to that statement. What is the clarification?

श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी: सभापति जी, उन्होंने माइनर पोट्‌र्स के बारे में प्रश्न किया है। ये हमारे देश में 184 हैं। इनकी डेवलपमेंट के लिए मैं बता दूं कि हम राज्य सरकारों के माध्यम से इसकी डेवलेपमेंट करते हैं । इन्होंने जो नया प्रश्न पूछा है कि इसके साथ साथ आप इन पोर्टस की डेवलेपमेंट के लिए क्या नीति अपना रहे हैं तो मैं बता दूं कि पोर्ट के लिए हम इस प्रकार के सर्वे पूरे करा रहे हैं। इस सर्वेज के माध्यम से, पोर्टस की डेवलपमेंट किस प्रकार की जाए, इसके लिए भी सोच रहे हैं।

PROF. M. SANKARALINGAM: In reply to part (c) of the question, it has been stated that an agreement has been signed between the Ministry of Shipping and M/s Tata Consultancy Services. I would like to know *ihe* terms of reference of this agreement.

श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी:सभापति जी, सर्वे के लिए एक टेंडर निकाला गया था। इसमें बारह लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें से चार इलिजिबल हुए थे। सबसे अच्छा टाटा कंसेल्टेंसी से एग्रीमेंट हुआ है। इन्होंने सात महीने के अंदर पूरा सर्वे करके रिपोर्ट देने की बात कही है।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Sir, Pondicherry is a minor port. I want to know whether any scheme has been received from the Pondicherry Government to improve the port of Pondicherry. If it has been received, what has been the response of the Government of India in this regard?

श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी: सभापति जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सभापति:विजय मल्लया जी, आप एब्सेंट थे। अगर 526 प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।

Schemes for welfare of tribes living in forests in Karnataka

*526. DR. VI JAY MALLYA: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of schemes/programmes being implemented for the welfare of tribes living in forests particularly in Karnataka;

(b) the details of steps taken/proposed to be taken by Government for providing alternative livelihood to such tribes due to shrinking forest areas; and

(c) the steps taken by Government for their upliftment?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM)); (a) to (c) The Ministry of Tribal Affairs implements several Central Sector/Centrally Sponsored Schemes/programmes for the socio-economic development of tribals in all the States/UTs, including Karnataka. These Schemes/ programmes are meant for the welfare of all the tribals, including those living in forests. There is no separate scheme specifically for the tribals living in forests or those affected due to shrinking forest areas.

The Schemes of the Ministry relate to income and employment generation, infrastructure development, educational development and improvement in literacy of all the tribals. Some Schemes pertain to ensuring fair prices for minor forest produce and food security for the tribals, besides the promotion of voluntary efforts in the area of tribal welfare. The list of Schemes/programmes o'f Ministry of Tribal Affairs, being imple-